

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग ।—खण्ड 1

PART I—Section 1

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 3, 2016 ∕वैशाख 13, 1938 No. 130] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 3, 2016/ VAISAKHA 13, 1938

## श्रम और रोजगार मंत्रालय (केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

## संकल्प

नई दिल्ली, 3 मई, 2016

- सं. यू-23013/30/2014-एलडब्ल्यू (बी).—इस मंत्रालय के दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 के संकल्प संख्या यू-23013/30/2014-एलडब्ल्यू और दिनांक 17 नवम्बर, 2015 के उत्तरवर्ती शुद्धि-पत्र के अधिक्रमण में तथा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा कांडला पोर्ट ट्रस्ट को उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रम संख्या 8(i), (ii) और (iv) में दिए गए कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन के संबंध में छूट प्रदान करने पर विचार करने हेत् एक समिति गठित करता है।
  - 2. इस समिति का संघटन और विचारार्थ विषय निम्नवत होंगे:-
    - (i) श्री आर. मोहन दास, —सदस्य निदेशक(कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध), कोल इंडिया लिमिटेट, 10, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता- 700001.
    - (ii) श्री विवेक मंटेरियो, —सदस्य सचिव, कार्यालय मुंबई श्रमिक संघ, क्वेरी रोड, भंडुप, मुंबई – 400078.
    - (iii) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), —सदस्य-संयोजक अहमदाबाद
  - 3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:—

"इस बात का अध्ययन करना कि ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 31 के तहत अधिसूचना का.आ. संख्या 319(अ) दिनांक 08.05.1991 के दृष्टिगत उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या

2196 GI/2016 (1)

8(i) में पोर्ट क्षेत्र में सफाई करने और कूड़ा कचरा तथा राख हटाने संबंधी क्षेत्र में, प्लंबिंग एवं बागवानी जिनसे नई योजनाओं का भाग बनता है और जिन्हें वाह्य एजेंसी के माध्यम से निष्पादित किया जाना होगा उन्हें छोड़कर प्लंबिंग एवं बागवानी, साफ-सफाई, स्वच्छता संबंधी क्षेत्र में और 8(iv) में दिए गए कार्यों में पोर्ट ट्रस्ट गेस्ट हाउस में कांडला पोर्ट ट्रस्ट को ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने से छुट प्रदान करने में क्या कोई औचित्य है।"

4. समिति का मुख्यालय अहमदाबाद में होगा। समिति पक्षों की नए सिरे से सुनवाई करेगी, निवेदनों, यदि हों, की अनुमित देगी तथा अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगी।

ए. के. सिंह. सचिव.

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (Central Advisory Contract Labour Board) RESOLUTION

New Delhi, the 3rd May, 2016

**No.** U-23013/30/2014-LW (B).—In supersession of this Ministry's Resolution No. U-23013/30/2014-LW dated 14<sup>th</sup> October, 2015 and subsequent Corrigendum dated 17<sup>th</sup> November, 2015 and in exercise of the powers conferred by section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to consider the Grant of exemption to Kandla Port Trust under Section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, against Notification S.O. No. 319(E) dated 08.05.1991 in respect of employment of Contract Labour in the works given in the schedule against Sl. No. 8 (i), (ii) & (iv) to the said Notification.

- 2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under:—
  - (i) Shri R. Mohan Das, —Member Director (Personnel and Industrial Relations), Coal India Limited, 10, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001.
  - (ii) Dr. Vivek Monterio,Secretary, Office of Mumbai ShramikSangh,Quarry Road, Bhandup, Mumbai 400078.
  - (iii) RLC (Central), Ahmedabad —Member Convenor
- 3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:—
  - "To study whether there is justification for grant exemption Kandla Port Trust under Section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, against Notification S.O. No. 319(E) dated 8.05.1991 prohibiting of employment of Contract Labour in the works given in the schedule Sl. No. 8(i) in the area of sweeping and removal of garbage and ash from the Port Area, 8(ii) in the area of plumbing and gardening works, conservancy, sanitation except plumbing and gardening works which form part of the new schemes and have to be carried out through out side agency and 8(iv) in the Port Trust Guest house to the said Notification.
- 4. The Headquarter of the Committee will be at Ahmedabad. The Committee shall hear the parties afresh, allow submissions, if any and submit its report within three months.

A. K. SINGH, Secy.

-Member